nt>

17.31 hrs

Title: Half-an-hour discussion regarding production of pulses.

डा.लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : माननीय सभापति जी, अभी हमने एक संकल्प के माध्यम से महत्वपूर्ण विाय पर चर्चा समाप्त की और उसके बाद एक दूसरे महत्वपूर्ण संकल्प पर भी चर्चा हमने प्रारम्भ की। इस आधे घंटे की चर्चा में देश में आज जो दलहन की स्थिति है, उनका उत्पादन और आयात-निर्यात है, उससे संबंधित प्रश्न यहां उपस्थित करना चाहता हूं। यह बात सही है कि कृाि वैज्ञानिकों ने और देश के मेहनतकश किसानों ने अथक परिश्रम करते हुए भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया है। लेकिन जिस रूप में हम दलहन और तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, अभी हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके हैं। इस दिशा में बहुत कुछ प्रयास पिछले दिनों हुए। लेकिन उन प्रयासों का परिणाम जिस रूप में हमारे सामने आना चाहिए, वह नहीं आया है। यदि हम पिछले वार्ों के आंकड़े देखें तो उनसे कुछ बातों का अंदाजा सहज ही लग जाता है। यह बात सही है कि पिछले दिनों जिस प्रकार से देश के अंदर और बाहर विश्व भर में लोगों की रुचि शाकाहार की तरफ बढ़ी है, दलहन की मांग भी उसी रूप में बाजारों में बढ़ी है। क्योंकि स्वास्थ्य के लिए प्रोटीन और जो अन्य आवश्यक चीजें होती हैं वे दलहन के जरिये विशो रूप से प्राप्त होती हैं और उस दृटि से दलहन के उत्पादन के बारे में चिंता करना स्वाभाविक है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि दलहन के उत्पादन के बारे में जितनी उपलब्धता होनी चाहिए वह उपलब्धता नहीं है और उसके कारण निरंतर भावों में वृद्धि हुई है। उसके पीछे दो-तीन कारण हैं। इनके उत्पादन की जो लागत आती है, उस लागत के अनुसार किसान को जो चीजें लगानी होती हैं जिसमें खाद, बीज, कृाि-उपकरण या अन्य साधन हैं, वे दिन-प्रतिदिन महंगे होते जा रहे हैं और उसके कारण जो लागत मूल्य आता है वह लागत मूल्य भी उसे नहीं मिल पा रहा है। इस दृटि से किसान की रुचि अन्य फसलों की तरफ बढ़ती जा रही है। जिसमें उसे ज्यादा लाभ दिखायी देता है। मैं इस प्रश्न के माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो-तीन विशो बातें जानना चाहूंगा। देश के अंदर एक राट्रीय दलहन विकास परियोजना है। अब यह राट्रीय परियोजना है, केन्द्र शासित प्रदेशों के अंदर इस परियोजना पर शत-प्रतिशत खर्च किया जाता है और जो देश के विभिन्न राज्य हैं उनमें 75-25 के हिसाब से खर्च किया जाता है। यानी केन्द्र 75 प्रतिशत देता है और 25 प्रतिशत राज्य सरकारों को वहन करना होता है। लेकिन मेरी जानकारी में आया है कि राज्य सरकारों की तरफ से मिलाया जाने वाला अंश जो 25 प्रतिशत है, वह राज्य सरकारें देने में प्राय: असमर्थ होती हैं और उस असमर्थता के कारण जो 75 प्रतिशत केन्द्र से मिलना चाहिए वह केन्द्र वाली राशि भी नहीं पहुंच पाती हैं। फलत: परियोजना का लाभ पूरा-पूरा नहीं मिल पाता है।

मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस परियोजना के बारे में यदि आप वास्तव में लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो जैसे केन्द्र शासित प्रदेशों में आपने व्यवस्था की है, क्या राज्यों में भी उसी प्रकार की व्यवस्था करेंगे ताकि किसानों को लाभ मिले और जो आप दलहन का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, वह बढ़े और इस योजना का लक्ष्य जो हमने तय किया है, वह हम प्राप्त कर सकें।

मैं निवेदन कर रहा हूं कि 1997-98 में और 1998-99 में राट्रीय दलहन विकास परियोजना के तहत दलहन का जो कुल प्राप्त किया उत्पादन था, विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय हिस्से के रूप में दी गई राशि थी, 1997-98 में और 1998-99 में जो उत्पादन हुआ वह थोड़ा कम हुआ। 1999-2000 में फिर उत्पादन कम हुआ। इस योजना पर जो खर्च होना था, 5,18,900 रुपये था। इसमें से केन्द्रीय हिस्सा 4 लाख से ऊपर था। उत्तर पूर्वी क्षेत्र की ओर अधिक ध्यान केन्द्रित करने की दृटि से इन राज्यों के लिए आबंटन केन्द्र ने 12 प्रतिशत और बढ़ा दिया है। जैसा मैंने कहा कि देश में दलहनों के उत्पादन की दृटि से किसानों के सामने जो कठिनाइयां होती हैं, उस दृटि से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन दलहनों में प्रायः विविध प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, कीटाणु लग जाते हैं। उन कीटाणुओं पर काबू पाने के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए क्या उपाय अपनाए जा रहे हैं? कृाि वैज्ञानिकों ने यद्यपि प्रयत्न किया है लेकिन फिर भी मैं एक रिपोर्ट के आधार पर उद्धृत कर रहा हूं --

> " देश में अभी भी दलहन उत्पादन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे वार्ा, सिंचित सीमांत और उप सीमांत भूमि पर इनकी खेती करना, कीट, कृमियों तथा रोगों का अधिक प्रभावशाली होना, मौसम संबंधी विचलन, आनुवंशिक सफलता और कमी, सिंचाई की अनुपलब्धता और दलहनी क्षेत्र को दूसरी अधिक लाभकारी फसलों में परिवर्तित कर देना। इन सीमाओं के अलावा दलहनों का उत्पादन मानसूनों पर भी निर्भर रहता है। दलहन उत्पदान जो 1990-91 में 14.26 मिलियन टन था, वह 1991-92 में घटकर 12.02 मिलियन टन रह गया और 1995-96 में यह और घट गया। 1996-97 में यह बढ़ा लेकिन 1997-98 में यह फिर घट गया और 12.97 मिलियन टन रह गया ।"

इस प्रकार से हमारे लिए यह भी चिन्ता का विाय है कि हम इस लगातार पिछले दस वार्ों में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैंने एक मूल प्रश्न जो पहले उपस्थित किया है क्या राज्य सरकारों को पूरी-पूरी सहायता या उनको पूरा अनुदान दिये जाने का माननीय मंत्री महोदय प्रबंध करेंगे और दूसरा किसानों के समक्ष जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करने की दृटि से आप क्या करने जा रहे हैं? एक और प्रश्न जो इसके साथ उद्भूत होता है कि अन्यान्य कई चीजों में समर्थन मूल्य हैं लेकिन इनके बारे में समर्थन मूल्य नहीं है। मसूर, मटर, आदि पर समर्थन मूल्य नहीं दिया जाता है लेकिन चने आदि में है। जिन बहुत सारी दलहनों का समर्थन मूल्य नहीं है, और उसके कारण वे किसान कई बार उन फसलों के उत्पादन में असमर्थ होते हैं, क्या माननीय मंत्री महोदय इस दिशा में भी कुछ प्रयत्न करेंगे कि उनका कोई समर्थन मूल्य हो और इस दृटि से माननीय मंत्री महोदय इस प्रश्न का भी उत्तर देने की कृपा करें।

मैं अभी निवेदन कर रहा था कि इस बारे में काफी वैज्ञानिक प्रयोग हो रहे हैं और मेरे क्षेत्र में भी एक सिपानी कृाि अनुसंधान केन्द्र है। उसने अरहर के बारे में काफी अनुसंधान किया है और इस प्रकार से विकास किया कि पांच महीने की अवधि घटकर लगभग तीन महीने में उत्पादन हो जाता है और उसका उत्पादन भी प्रतिशतता के आधार पर बढ़ा है।

मैं निवेदन कर रहा था कि जिस प्रकार से बीजों का रिप्लेसमेंट होना चाहिए, अभी हम तीन प्रतिशत बदलते हैं और हम प्रतिर्वा यदि लगभग 12 प्रतिशत बीज बदलें तब तो उत्पादन में वृद्धि होगी अन्यथा अभी जो बीज की रिप्लेसमेंट का प्रतिशत है वह केवल 3 प्रतिशत दलहन में है। कम से कम 10 प्रतिशत रीप्लेसमेंट हो तब भी विकास हो सकता है और उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। माननीय मंत्री महोदय बताएं कि इस प्रतिशतता को बढ़ाए जाने की दृटि से क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि देश की मांग के अनुसार और देश की आवश्यकता के अनुसार जो उत्पादन हो रहा है, और बढे आज भी हमें कई बार आयात पर निर्भर रहना पड़ता है और इसी कारण यहां दलहन का आयात हो रहा है।

सभापति महोदय, आज विदेशों से दलहन का आयात हो रहा है। अभी मैंने एक दाल मिल का निरीक्षण किया। मैंने वहां देखा मूंग दला जा रहा था और दाल बनाई जा रही थी। बहुत मोटा दाना था। मैंने मिल मालिक से पूछा तो उसने बताया कि यह बड़ा मूंग है। मैंने कहां यह कहां से आया, उन्होंने उत्तर दिया कि यह विदेश से आया है।

सभापति महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कृषि वैज्ञानिकों और किसानों के भरपूर प्रयत्न से हमारा देश अन्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। उसी प्रकार से हम दलहनों के मामले में भी आत्मनिर्भर हो सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि दलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के कार्यक्रम को आपने राट्रीय टैक्नौलौजी मिशन के अन्तर्गत लिया है, लेकिन तीन सालों से इसे राट्रीय टैक्नौलौजी मिशन के अन्तर्गत लेने के बावजूद जो उत्पादन बढ़ना चाहिए था, वह नहीं बढ़ा। इसके क्या कारण हैं। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इसका उत्तर देने की कृपा करेंगे।

सभापति महोदय, मैं जानता हूं कि इस दिशा में कुछ प्रयत्न हुए हैं, लेकिन प्रयत्नों की सफलता तभी आंकी जा सकती है जब हमारा उत्पादन बढ़े और हमारा आयात कम हो। यह ठीक है कि आज हम गेहूं और चावल के मामले में न केवल आत्मनिर्भर हो गए हैं और निर्यात करने जा रहे हैं बल्कि जिन देशों में संकट है, प्राकृतिक आपदा है या कठिनाइयां हैं, उन्हें अपने देश की ओर से हमारा देश गेहूं और चावल सहायता के रूप में दे रहा है। यह एक अलग बात है, लेकिन हमें आयात न करना पड़े और इसमें भी हम आत्मनिर्भर हो सकें, इस बारे में किए जा रहे प्रयासों से मंत्री महोदय सदन को अवगत कराएं।

सभापति महोदय, आज देशवासी दालें खाकर प्रोटीन और खनिजों की पूर्ति करना चाहते हैं। इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि दलहनों से उनके स्वास्थ्य का संरक्षण हो और जो भी प्रोटीन्स आदि आवश्यक चीजें हैं, वे उन्हें दालों के माध्यम से मिल सकें। इस प्रकार से देश में दलहनों की जो मांग बढ़ रही है उसको देखते हुए सरकार ने जो कदम उठाए हैं और जिस प्रकार से ठोस कदम उठाने का प्रयास करने जा रही है, उनसे सदन को अवगत कराया जाए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि बीजों के आधार पर, कुछ नए प्रयोगों के आधार पर, प्र ादर्शनों के आधार पर, स्प्रिंकलर सैटों और उन्नत किस्म के बीजों, औजारों और उपस्करों को देकर किसानों को इस बारे में प्रशिक्षण देकर आप दलहनों का उत्पादन बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि जो प्रश्न मैंने उद्भूत किए हैं, उनके उत्तर मंत्री जी देने की कृपा करें।

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : You have not given notice for that. Only four hon. Members have given prior notice. Therefore, only they will be allowed.

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, with regard to the question of production of pulses and oilseeds, I have a few specific questions. My first question is this: Are we importing oilseeds? Are we importing edible oil also and if so, why? What are the reasons for that? My second question is this: Are the pulses produced in India sufficient? Are we importing pulses also? If so, why? Hon. Member, Dr. Laxminarayan Pandeya has already mentioned about the National Technology Mission in which the oilseeds production has been included. I also wanted to put this question but since it has already been asked, I would like to know from the Minister what is the achievement of the National Technology Mission as far as oilseeds are concerned.

My third and very important question is regarding import of *vanaspati* oil from Nepal. In the last three years, the import of *vanaspati* oil from Nepal has increased by leaps and bounds. What is the reason for this? Due to import of *vanaspati* oil from Nepal at a very low price, a number of factories in Eastern India have started closing down. What is the reason? I would like to know how a poor country like Nepal is able to export *vanaspati* oil at low price to India and we are not able to compete with them price-wise.

My next question is about my own State, Orissa. While answering the question on 27th of last month the hon. Minister mentioned about production of pulses and crops in the unirrigated area in Orissa. Specifically in Western, South and the tribal districts of Orissa, there is a variety of pulse called Kandul. It is just like Arhar. It does not require much of water. It is generally grown by the Scheduled Tribe people for their own consumption. If the Government of India provide them some financial facilities, it can be developed as a commercial crop. I do not know if the hon. Minister and the Government of India knows about the production of Kandul. Will they come forward to provide some financial benefits or some other facilities so that it can be produced in a greater quantity?

Lastly, in the coastal Orissa, in the districts which I represent like Balasore, Bhadrak, Kendrapara, Cuttack and Puri, there is a lot of scope of developing oil seeds like sunflower, mustard and groundnut. They are being produced, but in a lesser quantity. Hardly any technological know-how is provided either by the Government of Orissa or by the Government of India. So, I would like to appeal to the hon. Minister to kindly look into it. The coastal Orissa provides a fertile ground for the production of oil seeds and pulses like Moong and Urad.

I hope that he would look into the matter and make provisions so that technological know-how, financial and economic assistance are provided to farmers of that area to enable them to produce it in a greater quantity.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि आज देश की आबादी एक अरब से अधिक हो चुकी है। देश में हरित क्रांति आयी और हरित क्रांति के बाद देश ने खाद्यान्नों के क्षेत्र में तो आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली लेकिन दलहन और तिलहन के मामले में अभी तक देश पूर्णरूपेण आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है। दलहन भी एक प्रकार से कैश क्रॉप है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूंगा कि राट्रीय दलहन विकास परियोजना के अन्तर्गत अधिक प्रोटीन वाली दालों के उन्नत बीजों के अनुसंधान के लिए अब तक क्या प्रयास किये गये हैं ?

मान्यवर, एक प्रवृत्ति चल रही है और अब लोग धीरे-धीरे मांसाहार से शाकाहार की ओर पुन: आ रहे हैं और शाकाहार के अंदर दालों का अपना महत्व है। दालों के अंदर प्रोटीन ज्यादा होगा तो लोग उसे और भी अधिक खाना पसंद करेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहूंगा कि राट्रीय दलहन विकास परियोजना तो बना ली लेकिन इसके माध्यम से अधिक प्रोटीन वाली दालों के उन्नत बीजों के विकास और अनुसंधान के लिए अब तक क्या प्रयास किये जा रहे हैं और क्या देश में दलहन ज्यादा पैदा करने वाले राज्यों या क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है ? यदि हां तो उन क्षेत्रों के किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की कोई विशेा योजना है ? क्या सरकार उनको विशेा अनुदान देना चाहेगी ?

तीसरी बात मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि और देशों में हमने देखा है कि दलहन के क्षेत्र में अनुसंधान हुए हैं, नये बीजों का आविकार हुआ है और उन्होंने अपना उत्पादन दुगुना-तिगुना कर दिया है। जबकि हमारे यहां भी अनुसंधान प्रयोगशालाएं वगैरह सब कुछ हैं। इसके बाद भी हमारे यहां अनुसंधानों का उतना प्रभाव दलहन के उत्पादन के क्षेत्र में क्यों नहीं परिलक्षित होता है ? इसके क्या कारण रहे हैं तथा सरकार की उपेक्षावृत्ति के कारण क्या हैं, इसके बारे में प्रकाश डालें तो अधिक अच्छा रहेगा।

कृि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक) : सभापति महोदय, माननीय डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय यहां जो डिस्कशन लाए हैं और जो प्रश्न उन्होंने पूछे हैं, उनके उत्तर देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। हम दुनिया में सबसे ज्यादा पल्सेस प्रोडक्ट कर रहे हैं। हम अपने देश में ग्यारह किस्म के पल्सेस का प्रोडक्शन कर रहे हैं। हमारे यहां पल्सेस का जो प्रोडक्शन होता है, वह लोक संख्या को देखते हुए सफीशिऐंट नहीं है, यह हम मानते हैं। यहां जो दलहन पैदा होता है, हम जिस जमीन पर दलहन पैदा करते हैं, वह बहुत कम है। दलहन का प्रोडक्शन सिर्फ रेनफैड एरिया पर अवलम्बित है। हमारी सरकार प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है। हमारी सरकार जो प्रयत्न कर रही है, हमें एक बात समझनी चाहिए कि जब बारिश कम होती है, उस समय प्रोडक्शन पर असर होता है। इस प्रोडक्शन में फ्लकचुइटी ज्यादा है इसलिए कम, ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है। इस वर्ा निश्चित रूप से प्रोडक्शन कम हुआ है और उसका कारण ड्राउट है।

प्रो. रासा सिंह रावत ने पूछा है कि जो राज्य ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, यू.पी. और महाराट्र, मैं बताना चाहता हूं कि टोटल प्रोडक्शन का 68 प्रतिशत प्रोडक्शन इन राज्यों में होता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात में टोटल प्रोडक्शन का 15 प्रतिशत प्रोडक्शन होता है। नैशनल पल्सेस डैवलपमैंट प्रोजैक्ट से पल्सेस प्रोडक्शन बढ़ाने की हमारी सरकार द्वारा हर तरह से कोशिश की जा रही है। हमने इसके अन्तर्गत 25 राज्य, 2 यूनियन टैरीटरी, 322 डिस्ट्रिक्ट्स में पल्सेस प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की है। तरह-तरह की स्कीम्स के अन्तर्गत पल्सेस प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भारत सरकार से राज्य सरकारों को 72-25 रेशियो पर फंड ऐलॉट करते हैं।

इनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इस बार इस शेयर रेश्यो में थोड़ी बढ़त की है। जैसे प्रोडक्शन ऑफ फाउंडेशन सीड के बारे में यहां प्रश्न आया। पहले टेंथ प्लान के अन्दर जो स्कीम थी, उसमें जो डवलपमेंट प्रोजैक्ट की स्कीम थी, उसमें 75: 25 से 400 रुपये प्रति क्विंटल प्र ाोडक्शन ऑफ फाउंडेशन सीड के लिए हम देते थे। अब इसको 100 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है। प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड सीड्स विलेज स्कीम थी, उसके अन्दर जो 200 रुपये प्रति क्विंटल था, उसको 500 रुपये प्रति क्विंटल किया है। इसी तरह हर स्कीम में सीड ट्रीटमेंट के लिए, डिमोन्स्ट्रेशन के लिए, प्रोटैक्शन के लिए, फार्मर्स ट्रेनिंग के लिए, इम्प्रूव्ड फार्मिंग इम्प्लीमेंटेशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्प्रिंकलर सैट्स के लिए, हर स्कीम में रकम बढ़ा दी गई है। नाइंथ प्लान में जो स्कीम बनाई हुई है, उसमें हमने पल्स प्र ाोडक्शन का एरिया एक्सपेंड करने के लिए भी प्रयास किये हैं। हमारी सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, इस एक्सपर्ट कमेटी से जो रिपोर्ट आई है, उसमें जो सजेशन दिये हैं, माननीय पांडे जी ने उसका सवाल हमारे सामने रखा हैâ€¦(व्यवधान)

श्री नरेश पुगलिया (चन्द्रपुर) : सैण्ट्रल गवर्नमेंट ने कितना पैसा खर्च किया, वह तो बतायें?

श्री श्रीपद यासो नाईक :सैण्ट्रल गवर्नमेंट ने पंचवर्ाीय योजना में से 36 करोड़ रुपया सारे देश के लिए दिया है। यह पैसा तो प्लानिंग कमीशन तय करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने तय किया है। हमारा तो इसके लिए एफर्ट चल रहा है, हम इस रकम से ऊपर नहीं जा सकते। एक्सपर्ट कमेटी ने जो सजेशन दिये थे, उन सजेशंस की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने -

> **"Inclusion of pulses in the cropping system to improve soil health and increase the area coverage; supply of quality seeds through integrated programme of seed production from breeder to foundation and foundation to certified/quality seed in sufficient quantities; promotion of gypsum/pyrite as a source of sulphur which increases the productivity of pulses; large scale promotion of sprinkler system which is very successful in pulse crop; greater attention to extension and technology transfer through demonstration and training; and popularisation of NPV for control of pod borer in *arhar* and gram. "**

जो सजेशंस एक्सपर्ट कमेटी ने दिये हैं, वे सजेशंस हमने इम्प्लीमेंटेशन के लिए ले लिये हैं।

DR. LAXMINARAYAN PANDEYA (MANDSAUR): Is it remunerative price or support price? I think you are not asking for that. समर्थन मूल्य के बारे में या प्रोत्साहन मूल्य के बारे में भी सरकार ने कोई विचार किया है कि इसको बढ़ाया जायेगा या नहीं बढ़ाया जायेगा ?

श्री श्रीपद यासो नाईक : जी हां। हम कोशिश कर रहे हैं और जो चार धान्य हैं, चना, अरहर, मूंग और उड़द, इन चारों धान्यों के लिए अभी तक हम सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं। मसूर को भी इसमें निश्चित रूप से जोड़ने के लिए कास्ट प्राइस निकालने के लिए हमने एक समिति गठित की है और मसूर को भी इसमें लेने का प्रावधान किया है।â€¦(व्यवधान) एक-एक करके ले लेंगे, एक बार में तो नहीं होगा। बोड़ोलैंड के

लिए हम स्पेशल स्कीम दे देंगे।□□ (*Interruptions*)

18.00 hrs.

MR. CHAIRMAN : Hon. Minister, you should reply to those questions which are raised by the hon. Members. Please confine to the questions raised by the hon. Members.

...(*Interruptions*)

श्री श्रीपद यासो नाईक : एक्सपर्ट कमेटी ने भी सीड के रिप्लेसमेंट के लिए सुझाव दिया है। अब तक तीन प्रतिशन दे रहे हैं, अब सरकार का दस प्रतिशत तक का इरादा है, उस पर विचार हो रहा है। माननीय सदस्य स्वैन ने टैक्नोलॉजी मिशन के बारे में और उसकी एचीवमेंट के बारे में पूछा था। अभी तक उस मिशन की एचीवमेंट रिपोर्ट हमें प्राप्त नहीं हुई है। काम शुरू है, जल्द से जल्द वह आपके सामने रख दी जाएगी।

वनस्पति के बारे में भी स्वैन जी ने कहा। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वनस्पति पल्सेज में नहीं आती। अगर आप चाहें तो मैं अलग से इस बारे में आपको बता दूंगा। दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं।

For increasing productivity, along with horizontal expansion through pure cropping or inter-cropping, attempts are being made to break the yield barriers by intensification of the existing improved technology. The basic elements of this are seeds, pest control measures, irrigation, fertilizers and low cost production enhancing inputs:

i. **Besides the existing infrastructure for seeds in the public and the cooperative sector, NGOs and other reputed private seed growers will also be associated for the production of certified seeds. To make the pulses crops competitive along with the price support mechanism, productivity is essential and, therefore, for achieving the desired seed replacement rate, new improved varieties will be distributed on a large scale and the public/cooperative seed production of agreed quantity by underwriting the sale of unlifted seed.**
ii. **In the cultivation of pulses which are being grown mostly in the rain-fed conditions, the existing facilities of subsidised distribution of sprinkler sets will be expanded. Under NPDP, the programme relating to sprinkler irrigation is being extended from year to year. This programme will have to be provided for a longer period, say 10 years or so.**
iii. **Extension support to farmers will be strengthened with the association of the NGO's farmers association along with the Government machinery.**
iv. **Integrated Pest Management Technology for pulses is still in a preliminary stage of its development and hence the use of eco-friendly plant protections chemicals would continue by the farmers. For encouraging the use of bio-control agents like NPV, their availability will be improved.**
v. **For increasing the productivity of pulses, ICAR has advocated the use of sulphur as pulses respond well to sulphur application. Materials like gypsum/pyrites have been identified as most suitable carriers of sulphur and as such its use will be popularised among the pulse growers through financial incentives.**

सरकार पल्सेज का उत्पादन बढ़ाने के लिए हर तरह से कोशिश कर रही है। भविय में इसका परिणाम भी सामने आ जाएगा। आप सबने जो सुझाव दिए हैं, वे ध्यान में रखे जाएंगे और उन पर विचार किया जाएगा।

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet again at 11 AM on 18th December, 2000.

18.04 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Monday, December 18, 2000 / Agrahayana 27, 1922 (Saka).